वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में आतिशबाजी

भोपाल(काप्र)।

राजधानी में वक्फ बिल 2024 को लेकर मुस्लिम समाज में खुशी का माहौल रहा। हताई खेड़ा डैम के पास आनंदपुरा कोकता में मुस्लिम समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए सडक़ों पर उतरे। यहां महिलाएं भी हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के पोस्टर लेकर सामने आए।

मुस्लिम समुदाय ने इस बिल के समर्थन में पोस्टर और फूल लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। इस उत्सव का हिस्सा बनते हुए लोग ढोल ताशे पर नाचते और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर करते रहें। इस दौरान मोदीजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं... नरेंद्र मोदी जिंदाबाद... जैसे नारे लगाए। वहीं, हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भोपाल के लोगों को अच्छी तरह पता है कि आरिफ नगर में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का सौदा कौन कर रहा है? कौन इसका पैसा खा रहा है? पहले कांग्रेस के सांसद इस संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे थे और अब कांग्रेस के विधायक इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इस संपत्ति का सही लेखा-जोखा किसके पास है? यह संपत्ति सही हाथों में होनी चाहिए ताकि सरकार गरीबों के उत्थान के लिए इसका उपयोग कर सके। विधायक शर्मा ने कहा कि हम गरीबी में रहने वाला हिंदुस्तान नहीं चाहते। अगर मुसलमान गरीब रहेगा तो उसकी जिंदगी पंचर की दुकान पर ही गुजर जाएगी। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था उन्नति कर रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों के बारे में सोचा है, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ कुछ गुंडे-बदमाशों के बारे में सोचा है।

चंद नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने समाज को गुमराह कर रहेः सारंग

वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चाओं के बीच मध्यप्रदेश के सहकारिता और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इस बिल का आम मुसलमान से कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि कुछ अमीर मुस्लिम नेता, जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर बेजा कब्जा किए बैठे हैं, वही इसका विरोध कर रहे हैं। श्री सारंग ने कहा कि भोपाल में हजारों मुस्लिम भाइयों और बहनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वक्फ संशोधन बिल का खुलकर समर्थन किया है। यह उन नेताओं के लिए करारा तमाचा है, जो इस बिल को लेकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बिल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सही उपयोग और आम मुसलमान के हित में लाया गया है।

दिवंगत जेल डीआईजी गांधी की पत्नी और भाई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज

भोपाल(काप्र)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के भोपाल ऑफिस ने दिवंगत जेल डीआईजी उमेश कुमार गांधी की पत्नी अर्चना गांधी और उनके भाई अजय कुमार गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यह मामला 29 मार्च 2025 को भोपाल की विशेष अदालत में दर्ज किया गया।

लोकायुक्त पुलिस ने उमेश कुमार गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। जांच में पता चला कि उनकी संपत्ति उनकी आय से कहीं ज्यादा थी। इसी के आधार पर ईडी ने आगे जांच की जिसमें पता चला की उमेश कुमार गांधी ने अपने परिवार और करीबी लोगों के नाम पर बड़ी संख्या में चल-अचल संपत्तियां खरीदी थीं। कुल 4.68 करोड़ रुपए की संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित की गई थीं। इनमें जमीन, बैंक बैलेंस, आभूषण, बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड और किसान विकास पत्र शामिल हैं। ईडी ने 3 जनवरी 2025 को इन संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था। इनमें सागर, कटनी, सीहोर, भोपाल और इंदौर में स्थित 20 अचल संपत्तियां (जमीन, मकान आदि) और फिक्स डिपॉजिट शामिल हैं। भोपाल में न्यायालय द्वारा इस मामले में संज्ञान लिए जाने पर ईडी ने लोकायुक्त पुलिस भोपाल द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जांच की थी। अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है।

राजधानी में बुधवार को मोती मस्जिद में शहर काजी के सामने हज यात्रा के लिए पर्ची निकाली गई।

लोकायुक्त अब पहरेदार नहीं, हिस्सेदार हैः नायक

सौरभ शर्मा को जमानत लोकायुक्त की नाकामी का प्रमाण

भोपाल(काप्र)।

मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा है कि मप्र में सौरभ शर्मा मामला लोकायुक्त और सरकार की मिलीभगत का ताजा उदाहरण बनकर सामने आया है। पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा, जिसके पास से करोड़ों रुपये की अघोषित संपत्ति, 52 किलोग्राम सोना और 11 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुई थी, को लोकायुक्त पुलिस की घोर लापरवाही के चलते विशेष लोकायुक्त अदालत से जमानत मिल गई।

निर्धारित 60 दिनों में चालान पेश न कर पाने की यह नाकामी कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है। इस पूरे प्रकरण में लोकायुक्त की संदिग्ध भूमिका और सरकार की चुप्पी जनता के सामने सच्चाई को उजागर कर रही है।

इस हाईप्रोफ़ाइल मामले की जांच के दौरान लोकायुक्त निदेशक जयदीप प्रसाद का अचानक ट्रांसफर इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि सरकार इस मामले को दबाने में जुटी है। जयदीप प्रसाद, जिन्होंने सौरभ शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर छापेमारी की थी, को हटाना स्पष्ट करता है कि बड़े रसूखदारों को बचाने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। मध्यप्रदेश में लोकायुक्त और सरकार की मिलीभगत से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का सिलसिला लंबे समय से जारी है। जहां लोकायुक्त अधिकांश मामलों में भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करती है, वहीं कार्रवाई की इच्छा होने पर भी सरकार अभियोजन की अनुमति रोककर अपराधियों की ढाल बन जाती है।

लोकायुक्त की कार्यप्रणाली अब एक निकम्मी और नकारा संस्था की हो चुकी है। यह पहरेदार की जगह हिस्सेदार की भूमिका में काम कर रही है। सौरभ शर्मा जैसे हाई-प्रोफाइल मामले में इसकी नाकामी ने साबित कर दिया कि लोकायुक्त पुलिस अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। लोकायुक्त, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों द्वारा सौरभ शर्मा के ठिकानों से बरामद बेशुमार संपत्ति के बावजूद जांच में ढिलाई, जयदीप प्रसाद का ट्रांसफर और निर्धारित समयावधि में चालान पेश न करना इस बात का संकेत है कि सरकार और लोकायुक्त मिलकर अपराधियों को खुली छूट दे रहे हैं। ऐसे में अब जरूरी हो गया है कि लोकायुक्त जैसी भ्रष्ट और औचित्यहीन संस्था को बंद कर दिया जाए।

बोलेरो से कर रहे थे शराब तस्करी, क्राइम ब्रांच ने दबोचा

भोपाल(काप्र)।

राजधानी की क्राइम ब्रांच ने दो ऐसे शराब तस्करो को दबोचा है, जो पुलिस की नजरो से बचने के के लिये बोलेरो वाहन से शराब तस्करी कर रहे थे। आरोपियो के पास से अग्रेंजी शराब सहित 2 लाख कीमत की 180 लीटर अवैध शराब जब्त की है।

शराब के साथ ही पुलिस ने बोलेरो वाहन भी जप्त किया है। आरोपी शहर के सीमावर्ती इलाकों में अवैध शराब की तस्करी करते थे। उनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी, कि दो युवक सफेद रंग की बोलेरो में शराब रखे हुए है, जो बेचने की फिराक में सरस्वती नगर मल्टी के पीछे थाना टीटी नगर में खड़े हुए हैं। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और बोलेरो जीप नजर आने पर घेराबंदी जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। ड्राइवर सीट पर बैठे लड़के से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दीपक कुचबदिया पिता थान सिंह कुचबदिया (33) निवासी अटल अयुब नगर थाना गौतम नगर भोपाल और बगल वाली सीट पर बैठे युवक के ने अपना नाम छविकांत सिरोडे पिता अर्जुन सिरोडे (26) निवासी शंकर नगर एफसीआई गोदाम के पीछे थाना छोलामंदिर भोपाल का बताया। बोलेरो की तलाशी लेने पर कार में बीच वाली सीट व पीछे की सीट पर 20 पेटी बैग पाइपर विस्की मिली जिसके संबंध में दोनो संदेहियों से पूछताछ करने पर वह शराब स्वयं की होना बताया दोनों आरोपियो को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया की पकड़े गये तस्कर निजी काम करते है, और आदतन अपराधी है, उनके खिलाफ अलग-अलग थानो में कई प्रकरण दर्ज है।

पार्थ योजना और खेलो-बढ़ो अभियान को करें क्रियान्वितः सारंग

भोपाल(काप्र)।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने पार्थ (पीएआरटीएच) योजना और खेलो-बढ़ो अभियान के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये है। उन्होंने कहा है कि पार्थ योजना और खेलो-बढ़ो अभियान के जरिये ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी इससे लाभान्वित हो, इसकी तैयारी की जाये।

श्री सारंग बुधवार को तात्या टोपे स्टेडियम स्थित मेजर ध्यान चंद हॉल में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने दोनों योजना और अभियान को मूर्तरूप से धरातल पर उतारने को कहा। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 9-10 संभाग में इसको त्वरित गति से अग्रसर किया जाये। इसकी विभाग और शासन स्तर की कार्रवाई पूर्ण करें और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाये। श्री सारंग ने कहा कि खेलो-बढ़ो अभियान 1 मई से शुरू हो। प्रारंभ में इसके लिये 37 जिले चयनित किये गये है। सोशल मीडिया से भी इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाये, जिससे प्रदेश का टैलेन्ट सामने आये। इसका कैलेण्डर तैयार कर लिया जाये। साथ ही बच्चों के पालकों के साथ भी मोटिवेशन वार्तालाप हो। श्री सारंग ने निर्देश दिये कि सितम्बर से खेलो एमपी गेम्स की शुरूआत की जाये, जिससे मध्यप्रदेश की टीम तैयार हो और वही नेशनल चैम्पियनशिप में भाग ले। बैठक में भेल स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, खेलो एमपी यूथ गेम्स, प्रकाश तरूण पुष्कर, फिट इंडिया क्लब और नेशनल चैम्पियनशिप पर भी चर्चा की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव, खेल संचालक राकेश गुप्ता, संयुक्त संचालक बीएस यादव उपस्थित थे।

वन विभाग ने 1600 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया

भोपाल(काप्र)।

वन विभाग की कुशल नीति, वन उत्पादों के प्रबंधन, डिजिटल प्रणाली और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप राजस्व में वृद्धि हो रही है। वन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1600 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह वन विभाग की अब तक की सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 200 करोड़ रुपये से अधिक है। वन विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में 1425 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया, वर्ष 2022-23 में 1400 करोड़ और वर्ष 2021-22 में 1444 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था।

वन विभाग को प्राप्त राजस्व में सबसे बड़ा योगदान टिम्बर की बिक्री से हुआ है। इस वर्ष विभाग द्वारा टिम्बर बिक्री से 850 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। वन विभाग की नीलामी प्रक्रिया और बढ़ती मांग के कारण टिम्बर की बिक्री में वृद्धि हुई है। इसके अलावा अन्य वानिकी उत्पादों और पर्यावरण से जुड़े शुल्क से भी आय में वृद्धि हुई। वन विभाग को राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने से राजस्व में वृद्धि हुई है। ऑनलाइन चालान से विभाग को 1528 करोड़ की आय हुई, जबकि ट्रांसफर चालान से 763 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है।

स्पेशल खबर *भोपाल हाट बाजार में मिलेट दीदी कैफे और...*

विकास भवन में मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया दीदी कैफे का शुभारंभ

भोपाल(काप्र)।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्म-निर्भर एवं स्वावलंबी बनाना है।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित आजीविका स्वाद संगम (दीदी कैफे) ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि करने का साधन बन रहे हैं। श्री पटेल ने कहा कि स्व-सहायता समूह न केवल ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर रहे हैं बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बढ़ा रहे हैं। श्री पटेल ने बुधवार को विकास भवन एवं भोपाल हाट बाजार ने समूहों द्वारा संचालित आजीविका स्वाद संगम (दीदी कैफे) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी, सीईओ एसआरएलएम श्रीमती हर्षिका सिंह, सीईओ आरआरडीए दीपक आर्य, आयुक्त मनरेगा अवि प्रसाद सहित अधिकारी-कर्मचारी और स्व-सहायता समूहों की महिलाएं उपस्थित रही। श्री पटेल ने कहा कि शास्त्रों एवं परंपरागत ज्ञान में उल्लेख है कि भोजन में स्वाद भोजन सामग्री के साथ ही बनाने वाले के भाव का भी होता है। दीदी कैफे में भोजन स्वादिष्ट है क्योकि इसे तैयार करने वाली महिलाओं का अपनापन इसमें शामिल है। उन्होंने भोपाल हाट बाजार में मिलेट से तैयार व्यंजनो के लिए कैफे स्थापित करने की पहल की सराहना की। उन्होंने दोनों कैफे का अवलोकन कर व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने समूह की महिलाओं से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। श्री पटेल ने कैफे में सफाई व्यवस्था एवं कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। विकास भवन स्थित कैफे का संचालन संगम सीएलएफ के आठ समूह सदस्यों एवं हाट बाजार मिलेट कैफे का संचालन उड़ान सीएलएफ की पांच समूह सदस्यों द्वारा किया जा रहा है।

आजीविका स्वाद संगम (दीदी कैफे): आजीविका स्वाद संगम (दीदी कैफे) मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के क्लस्टर डवलपमेंट के तहत एक पहल है, जिसमें स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें तकनीकी समर्थन एवं वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है। इससे वे स्वयं के द्वारा संचालित कैन्टीन, केटरिंग ऑपरेशन, कियोस्क और फूड ट्रक जैसे खाद्य आधारित उद्यम स्थापित कर सकें। राज्य में आजीविका स्वाद संगम के विभिन्न खाद्य उद्यम स्थापित किए गए हैं जिसमें, स्व-सहायता समूह की प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमी अपने स्वाद के आधार पर आजीविका के नये आयाम विकसित कर रही हैं। इन दीदीयों द्वारा प्यार से तैयार किया गया, प्रत्येक व्यंजन कौशल, परंपरा और अटूट समर्पण का प्रमाण हैं। दीदी के हाथों से बने पकवानों का स्वाद, उनके स्वावलंबन, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का अनुभव कराता है। अपने प्रयासों से, ये दीदीयाँ अपनी उद्यमशीलता की भावना और सामुदायिक उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता से भी प्रेरित करती हैं।